

28 सितंबर, 2024
आर्थिक, कृषि पत्र, एकादशी
संवत् 2081
पृष्ठ : 12, मूल्य : ₹3.00

* ओडिशा संस्करण

www.epaper.azadsipahi.in

सीजीएल परीक्षा की
हकीकत का पता नहीं,
बस भीड़िया ट्रायल
चल रहा: हमें

रांची

शनिवार, वर्ष 09, अंक 338

आजाद सिपाही



अबुआ आभाद हेमन्त सरकार



नियुक्ति नियमावली में अड़चनों को दूर कर नियुक्तियों की कठियां जोड़ती हेमन्त सरकार

नव चयनित 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन
एवं मंत्रीगण सौंपेंगे नियुक्ति पत्र

दिनांक: 28 सितम्बर, 2024 | समय: अपराह्न 12:00 बजे | स्थान: जैप-1 ऑडिटोरियम, डोरण्डा, रांची

युवाओं के सपने, हेमन्त सरकार के हैं अपने

- कृषि पदाधिकारी समेत कई पदों पर राज्य गठन के बाद पहली बार नियुक्ति
- विभिन्न विभागों में हजारों युवाओं की हुई नियुक्ति
- JPSC अथवा JSSC द्वारा अनुरूपित विभिन्न पदों में 75% से 100% झारखण्ड के अभ्यर्थियों की नियुक्ति
- इस वित्तीय वर्ष में 5,403 स्नातक प्रशिक्षित एवं 539 लैब सहायकों की नियुक्ति
- JSSC द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में चयनित 327 अभ्यर्थियों एवं Re-counselling के उपरांत चयनित 200 सहायक एवं अधिकारी पदों की नियुक्ति
- गरीब-गुरुबा परिवार के युवा बने अफसर
- JPSC में एकार्ड समय पर नियुक्ति
- निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण के साथ 1 लाख से अधिक युवाओं को मिला ऑफर लेटर



राज्यपाल संतोष गंगवार ने दी खनिजों पर सेस लगाने की मंजूरी

4000 करोड़ का लाभ होगा

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक-2024 पर अपनी स्वीकृति दे दी है। जिसके बाद अब गणराज्य प्रकाशन के साथ ही राज्य में यह कानून लागू हो जायेगा। इस कानून के तहत राज्य में खनिजों पर सेस यानी उपकर लोगेगा।

राज्यपाल ने विधानसभा से परिवर्त विधेयक को दी स्वीकृति : यह विधेयक विधानसभा से परिवर्त होकर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। इसके तहत झारखंड की खनिज धारित भूमि से खनिज के उत्कर्षन पर रंगलटी पर उपकर (सेस) लगाने और इससे प्राप्त होनेवाली राशि से राज्य में आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्थात् प्राप्त होगा।

राज्य की इन आवश्यक उद्देश्यों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सेवाएं, कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पेयजल एवं स्वच्छता सहित अन्य



सुप्रीम कोर्ट से मिला था आदेश

इस मामले में 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने खदानों की भूमि पर सेस लगाने का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में राज्यों को खनिजों वाली जमीन पर उपकर (सेस) लगाने का अधिकार दिया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि सेस से मिलने वाली राशि सरकार द्वारा राज्य के विकास पर खर्च की जायेगी।

आवश्यकताएं शामिल हैं। इस विधेयक को स्वीकृति मिलने और राज्य सरकार को लाभ होगा। राज्य में सेस लागू होने पर खान विभाग को 2000 से लेकर 4000 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त राज्यव्यवस्थक विकास के लिए भेजा जायेगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने लाभ देने वाली है। जो अब बढ़ने वाली है।

वसूली का अनुमान है, जिससे राज्य सरकार को लाभ होगा। वर्तमान में खान विभाग का राज्यव्यवस्थक करीब 12 हजार करोड़ का है, जो अब बढ़ने वाली है।

राज्य की इन आवश्यक उद्देश्यों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सेवाएं, कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पेयजल एवं स्वच्छता सहित अन्य



